भगवान परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया आज

दैनिक

नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(सागर : वर्ष 12 अंक 39 ,पृष्ठ 12)
बुधवार 30 अप्रैल 2025
सागर संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... डा.अंबेडकर केवल दलितों के नहीं...

खेल... भारत में फुटबाल को मिलेगा नया बूस्ट ..

व्यापार... सीसीपीए ने सेवा शुल्क वापस न करने ....

देश-विदेश... कनाडा के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री...

www.naiduniaonline.com

हाई लेवल मीटिंग के बाद मोदी ने सेना को दी छूट, कार्रवाई कब और कहां वही तय करेगी

कहा- आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प

नई दिल्ली (काप्र)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

इस बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। मोदी ने सुरक्षा बैठक में कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय निर्धारित करने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। यह ऐसे समय में हुआ है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं, मामले से परिचित सूत्रों ने एएनआई को बताया। सूत्रों के अनुसार, चल रहे अभियानों की संवेदनशील प्रकृति के कारण इस स्तर पर कोई विशेष अपडेट साझा नहीं किया जा रहा है। सोमवार को, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने और आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की। यह ऐसे समय में हुआ है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस बीच, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में कई स्थानों पर गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं, मामले से परिचित सूत्रों ने एएनआई को बताया। सूत्रों के अनुसार, चल रहे अभियानों की संवेदनशील प्रकृति के कारण इस स्तर पर कोई विशेष अपडेट साझा नहीं किया जा रहा है। सोमवार को, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने और आतंकी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की। दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें तीन अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों और दो अन्य सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह बैठक जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के बीच आयोजित की गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर सैलानी थे।

मोदी आज करेंगे सीसीएस की बड़ी बैठक, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 अप्रैल को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो पलगाम आतंकवादी हमले के बाद दूसरी ऐसी बैठक होगी। फलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। वहीं, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 23 अप्रैल को बैठक की थी और आतंकी हमले की निंदा की थी। अन्य उपायों के अलावा, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की।

मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ....

नई स्थानांतरण नीति को मिली मंजूरी प्रदेश में 1 से 30 मई तक होंगे तबादले

भोपाल (काप्र)।

कैबिनेट ने 2025 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। 30 मई तक ई-ऑफिस में सभी स्थानांतरण लागू होंगे।

इसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो मान्य नहीं होगा। मंत्री और राज्य के मंत्रियों को स्थानांतरण के अधिकार दिए गए हैं। स्थानांतरण दो आधारों पर होंगे। पहला प्रशासनिक और दूसरा स्वैच्छिक (स्वेच्छा से)। कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति की अधिकतम सीमा पदों की संख्या के आधार पर तय की है। इसमें 200 पद तक-20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक-15प्रतिशत, 1001 से 2000 तक -10 प्रतिशत, 2001 से अधिक-5प्रतिशत तक स्थानांतरण हो सकेंगे। स्वैच्छिक तबादले भी स्थानांतरण के लिए तय प्रतिशत सीमा में शामिल रहेंगे, ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादलों का प्रतिशत बना रहे। इस दौरान हर विभाग अपने अनुसार नीति बना सकता है, लेकिन उसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी। कैबिनेट ने राज्य में 2000 मेगावॉट के सोलर पार्क और 1000 मेगावॉट की ऊर्जा भंडारण परियोजना लगाने को मंजूरी दी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा जरूरतों के अनुसार बनेगी।

इस परियोजना से दोनों राज्यों को पृथक-पृथक छह महीनों के लिए बिजली उपलब्ध होगी। इसकी स्थापना मुरैना जिले के आसपास की जाएगी। एमपी में रबी सीजन (अक्टूबर से मार्च) में बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, जबकि यूपी में खरीफ सीजन (जून से अक्टूबर) में। इसलिए दोनों राज्यों की बिजली जरूरतें एक-दूसरे की पूरक हैं। इससे बिजली का संतुलित उपयोग होगा। सरकार ने 1 जनवरी

2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है। समिति में अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन मध्य प्रदेश जेके शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में कुल 6 अधिकारी शामिल हैं और इनके काम में बदलाव या ट्रांसफर की स्थिति में वित्त विभाग के सचिव को बदलाव करने का अधिकार होगा।

यह समिति केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2024 से डीए में 3प्रतिशत की बढ़ोतरी कर कुल 53प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2प्रतिशत की बढ़ोतरी कर कुल 55प्रतिशत कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को छठवां या पांचवां वेतनमान मिलता है, उनके लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला अनुपात में लिया जाएगा।

भारत को हर प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में हो रहा काम

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार का प्रयास युवाओं को ऐसे कौशल से सशक्त बनाना है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें।

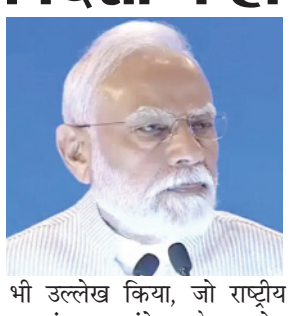

श्री मोदी ने मंगलवार को यहां भारत मंडपम में युग्म नवाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन के माध्यम से भारत की नवाचार क्षमता और डीप-टेक में इसकी भूमिका को बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलेगी। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और मुंबई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता , जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुपर हब के उद्घाटन का जिक्र किया। उन्होंने वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क के शुभारंभ का भी उल्लेख किया, जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से अनुसंधान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री ने वाधवानी फाउंडेशन, प्रौद्योगिकी संस्थानों और इन पहलों में शामिल सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने में रोमेश वाधवानी की समर्पण और सक्रिय भूमिका की भी विशेष सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक शिक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, शिक्षण सामग्री और कक्षा एक से सात तक के लिए नई पाठ्यपुस्तकों के विकास पर टिप्पणी की। उन्होंने पीएम ई-विद्या और दीक्षा प्लेटफार्मों के तहत एआई-आधारित और स्केलेबल डिजिटल शिक्षा अवसंरचना मंच - एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना के निर्माण पर प्रकाश डाला, जिससे 30 से अधिक भारतीय भाषाओं और सात विदेशी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा सकेंगी।

5 जून तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण काम

अयोध्या (एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण इस साल 5 जून तक पूरा हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर परिसर में स्थित महर्षि वाल्मीकि, श्री वशिष्ठ जी, अहिल्या जी, निषादराज महाराज, शबरी माता और अगस्त्य मुनि के मंदिर भी 5 जून के बाद आम जनता के लिए खुल जाएंगे। राम दरबार और मंदिर के परकोटे पर बने छह मंदिरों की पूजा 5 जून को होगी। चंपत राय जी 5 जून के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण पूरा होने के दिन यानी 5 जून के एक-दो दिन बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित सभी अलग-अलग मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार की सुबह आध्यात्मिक महत्व का एक ऐसा क्षण सामने आया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। वैशाख शुक्ल द्वितीया के शुभ दिन मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 फुट ऊंचा एक भव्य ध्वज दंड स्थापित किया गया। सुबह 6.30 से 8.00 बजे के बीच आयोजित यह पवित्र समारोह न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार का प्रतीक था, बल्कि मंदिर और ब्रह्मांड के बीच दिव्य संबंध का भी प्रतीक था।

सुको ने महिला को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, कहा

काजी अदालतों और शरिया को कानून में कोई मान्यता नहीं

नई दिल्ली (काप्र)।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में इस बात की पुष्टि की है कि सभी शरिया अदालतें, जिनमें काजी अदालतें, दारुल कजा या काजियात अदालतें के रूप में संदर्भित संस्थाएं शामिल हैं, भारतीय कानून के तहत कोई कानूनी दर्जा नहीं रखती हैं और इन निकायों द्वारा जारी किए गए निर्देश या निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं, न ही उन्हें कानूनी तरीकों से लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एक मुस्लिम महिला की अपील पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक पारिवारिक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था। वर्तमान मामले में पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर भरण-पोषण देने से मना कर दिया था कि वह वैवाहिक कलह के लिए जिम्मेदार थी। इसका निष्कर्ष मध्य प्रदेश के भोपाल में एक काजी अदालत के समक्ष प्रस्तुत समझौता विलेख पर काफी हद तक निर्भर था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय कानूनी अधिकारों का निर्धारण करने के लिए शरिया अदालतों जैसे गैर-न्यायिक निकायों की घोषणाओं पर भरोसा नहीं कर सकते।

चार धाम यात्रा आज से शुरू

नई दिल्ली (काप्र)। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। पिछले साल जहां 48 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने चार धाम की यात्रा की थी, वहीं इस बार 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने की उम्मीद है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हुआ था, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 20 लाख तीर्थयात्री चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि चार धाम कैसे पहुंचें, कहां ठहरें और इस यात्रा पर कितना खर्च आएगा।

भारत का लड़ाकू विमान गिराने का पाकिस्तानी सेना का दावा झूठा और निराधारः सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने पाकिस्तान समर्थित अनेक सोशल मीडिया खातों में भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान को गिराये जाने के दावे को झूठ बताते हुए कहा है कि यह भ्रामक तथा निराधार दुष्प्रचार है और भारत का कोई विमान नहीं गिराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अनेक सोशल मीडिया खाते झूठा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारत के राफेल लड़ाकू विमान को गिरा दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया है।

बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद में अवैध बस्तियां धवस्त

अहमदाबाद (एजेंसी)। अहमदाबाद में नगर निगम अधिकारियों और पुलिस ने मंगलवार को चंदोला झील क्षेत्र में एक बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। कुछ दिन पहले ही झील के आसपास बसी बस्तियों से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल के नेतृत्व में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। इस अभियान का जायजा लेने झील पर पहुंचे मलिक ने संवाददाताओं को बताया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र चंदोला झील में तोड़फोड़ अभियान के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए शहर के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। सिंघल ने बताया कि एएमसी ने तड़के 50 टीम के साथ अभियान शुरू किया, जिनमें से प्रत्येक के पास एक बुलडोजर था। उन्होंने कहा कि चंदोला झील पर आखिरी बार ध्वस्तीकरण अभियान 2009 में चलाया गया था। हाल ही में, एएमसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि सरकारी भूमि पर फिर अतिक्रमण कर लिया गया है।